भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-3587**
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

**ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता**

3587. **श्री गोपाल जी ठाकुर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना के अंतर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को लगभग 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;
(ख) यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि, अब तक जारी की गई धनराशि तथा विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त धनराशि का उपयोग करके विश्वविद्यालय में निर्मित अथवा अद्यतन किए गए भवनों, शैक्षणिक अवसंरचना, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, डिजिटल सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;
(घ) स्वीकृत की गई उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो पूरी हो चुकी हैं, वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा लंबित हैं और उनके लंबित रहने के कारणों और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त 100 करोड़ रुपये के उपयोग की समीक्षा और लेखापरीक्षा कराए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ङ): सरकार ने 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में शुरू किया है, जिसमें आरयूएसए के पिछले चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वंचित या कम सुविधा वाले क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पीएम-उषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के कुछ खास विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है ताकि निर्धारित नियमों और मानकों का पालन सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे को मजबूत

करने के लिए सहायता दी जाती है जिसमें छात्रावास, शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाएं और उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य ज़रूरी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। पीएम-उषा परियोजना को पूरा करने के लिए इस योजना को दिनांक 31 मार्च, 2028 तक और बढ़ा दिया गया है।

पीएम-उषा के तहत, इसके 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु)' घटक के अंतर्गत ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (U-0068), दरभंगा को कुल 100 करोड़ रुपये की राशि के अनुमोदन सहित बिहार राज्य के लिए कुल 388.85 करोड़ रुपये की लागत वाली 25 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

पीएम-उषा के अंतर्गत मिलने वाली निधि सहायता से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने जी+3 शैक्षणिक ब्लॉक भवन, बालिका छात्रावास, इनक्यूबेशन और नवाचार प्रकोष्ठ आदि के निर्माण; विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाओं, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर आदि के जीर्णोद्धार; डिजिटल सशक्तीकरण के लिए विभिन्न आईटी उत्पाद आदि खरीदने का प्रस्ताव किया है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत जून 2026 से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के अनुसार, परियोजना का कार्य जारी है, जिसमें 38 प्रतिशत कार्य हो गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में, राज्य को विभिन्न घटकों के अंतर्गत उपयोग के लिए 18.50 करोड़ रुपये की मूल संस्वीकृति प्रदान की गई है।

शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की ज़िम्मेदारी है। इस योजना के तहत सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर योजना की नियमित लेखा परीक्षा की जाती है। विभिन्न सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के व्यय संबंधी लेखा परीक्षित विवरणों के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आगे का अनुदान जारी करने के लिए उनसे एक समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) मांगा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों (एसएचईसी) के साथ मिलकर इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समीक्षा बैठकों और प्रत्यक्ष दौरों आदि के माध्यम से कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करती हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसएनए-स्पर्श मॉडल के माध्यम से निधि जारी की जाती है। एसएनए-स्पर्श मॉडल के अंतर्गत, निधि 'ठीक समय पर' जारी की जाती है और वेंडरों तथा लाभार्थियों को पीएफ़एमएस पोर्टल पर बिल जमा करने के आधार पर दैनिक संस्वीकृति जारी करके सीधे भुगतान प्राप्त होता है।

*****